खरीफ मार्केटिंग सीज़न है, वह October से next September तक चलता है, क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, जहां पर धान की दो फसल भी होती है, तो right from अक्तूबर से सितंबर तक धान की फसल होती है और एफसीआईएन जहां तक क्योंकि जब यह क्वेश्चन ही है और किसान का अनाज एफसीआई के माध्यम से और स्टेट एजेंसी के मार्फत प्रोक्योर किया जाता है, अनाज जो धान वगैरह है और जहां तक छत्तीसगढ़ का है, अभी तक 40 लाख टन के करीब धान प्रोक्योर हो चुका है और अभी तक जारी है।

श्रीमती छाया वर्माः सर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि गरीब आदमी रेग लेकर दूसरे आदमी की खेती करता है, किसानी करता है, लेकिन जो बोनस का पैसा होता है, वह खेती करने वाले को नहीं मिलता है। वह बोनस का पैसा जिसकी जमीन होती है, उसके खाते में चला जाता है। मैं पूछना चाहती हूं कि सरकार इसके लिए क्या कदम उठाएगी?

श्री सी. आर. चौधरीः महोदय, हमारा जो सिस्टम है, procurement खातेदार से किया जाता है। जो स्वयं खातेदार है, उसके मार्फत ही procurement होता है। जहां तक sub-tenant का सवाल है, उसका कोई प्रावधान नहीं है लेकिन tenant अपनी जमाबंदी के साथ, कि मेरा इतना अनाज पैदा हुआ है और इसमें से मैं इतना दे रहा हूं, तो उसी को दिया जा रहा है। Sub-tenant के नाम से कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन अगर दो काश्त के, tenant-2 and tenant-3 tenants हैं, एक ही खाते में चार नाम हैं तो चारों में से proportionately लिया जाता है। दूसरा जो आप बता रही हैं, उस प्रकार का प्रावधान है ही नहीं।

श्री सभापतिः रामविलास जी, यह विषय थोड़ा नाज़ुक है, लेकिन practical है। आगे इसके बारे में आप लोग आपस में स्टडी कीजिए। Sub-tenant गांव में क्या होता है, आपको भी मालूम है।

श्री रामविलास पासवानः सर, हम लोग इस बारे में सोच रहे हैं और इस संबंध में हम लोग आपसे भी मिलेंगे।

श्री सभापतिः ठीक है, धन्यवाद। प्रश्न संख्या 251

Remedial measures to extend help to loss making farmers

*251. SHRI A. VIJAYAKUMAR: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government is aware that high yield of vegetables, such as onions, tomatoes, brinjals, etc., caused loss to farmers in the country;

(b) if so, the remedial measures taken to extend help to loss-making farmers; and

(c) whether Government has any proposal to train farmers to make value-added products from the yield, such as onions, tomatoes, brinjals, etc.?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI RADHA MOHAN SINGH): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) No Sir, high yield of vegetables such as onion, tomato and brinjal has not caused loss to farmers in the country. The demand for fresh vegetables in the country is increasing due to population growth and change in dietary habits. In order to meet the demand, production and productivity of vegetables has increased due to interventions of Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) and other schemes of Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare. However, in the absence of efficient supply chain infrastructure, the perishability of produce sometimes causes losses to farmers. In order to minimize such losses, Government of India is implementing various schemes for creation of post-harvest infrastructure.

Ministry of Agriculture and Farmers Welfare is implementing Mission for Integrated Development of Horticulture for development of horticulture including creation of infrastructure for post-harvest management such as cold storages, processing units, pack houses, pre-cooling units, controlled atmosphere storage, reefer vans, integrated cold chain and low cost onion storage etc.

Ministry of Food Processing Industries is implementing Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana (Scheme for Agro-Marine Processing and Development of Agro-Processing Clusters) for creation of modern infrastructure with efficient supply chain from farm gate to retail outlets so, that farmers can get better prices for agricultural and horticultural commodities. Ministry of Food Processing Industries has also launched a new Scheme "Operation Greens" for tomato, onion and potato crops to promote agri-logistics and processing facilities through Farmer Producers Organization (FPOs) with professional management.

To protect the growers of perishable horticulture commodities from making distress sale in the event of a bumper crop during the peak arrival period when the prices tend to fall below economic levels and cost of production, Government is implementing Market Intervention Scheme (MIS). In addition to this, Government is working on creation of an institutional mechanism, with participation of all concerned Ministries, to develop appropriate policies and practices for price and demand forecast. This will help horticulture farmers to take informed decisions.

(c) Various institutes of Indian Council of Agricultural Research (ICAR) like IIHR Bengaluru, Directorate of Onion and Garlic Research (DOGR), Pune are providing hand-on practical training to farmers for making value added products of tomato and onion. Further, Government is providing training through Mission for

Integrated Development of Horticulture and scheme of "Support to State Extension Programs for Extension Reforms" popularly known as ATMA for latest agricultural technologies and good agricultural practices in different thematic areas including value added products of crops of agriculture and allied sectors to farmers to increase farm income.

SHRI A. VIJAYAKUMAR: Sir, during the season time, throughout India, there is excess production of tomato, brinjal and other vegetables. Excess production is there. Sometimes we also see in the TV, in our State also, that people are throwing tomatoes in the streets. Will the Government take any steps to market that during the season?

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, यह निश्चित है कि आपूर्ति श्रृंखला की बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण कभी-कभी किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ता है, इसीलिए राज्यों के माध्यम से जो बागवानी विकास मिशन है, उसके माध्यम से शीत भंडारण गृह, प्रोसेंसिग इकाई, pack house, pre-cooling इकाई आदि तथा किसानों के लिए उसमें सब्सिडी की गुंजाइश है। यह मिशन पूरे देश में प्रारम्भ हुआ है। पहले अधिकतर हम कोल्ड स्टोरेज बनाते थे, अब कोल्ड चेन बन रहा है, लेकिन मुख्य रूप से जो हमारी फूड प्रोसेंसिग मिनिस्ट्री है, उसने प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना देश में प्रारम्भ की, जिसके तहत 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है और जो इस प्रकार के फल और सब्जियां हैं, उनकी प्रोसेंसिग के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्टोरेज के लिए बड़े पैमाने पर देश भर में काम प्रारम्भ हुआ है। अभी पिछले बजट में आलू, प्याज और टमाटर के लिए एक नयी योजना चली है, जिसके तहत राज्यों के अंदर बड़े पैमाने पर — क्योंकि टमाटर, आलू और प्याज, इन तीनों की समस्या ज्यादा होती है, तो मंत्रालय का फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है और इस दृष्टि से इस योजना का लाभ भी अब बड़े पैमाने पर राज्यों को मिलना प्रारम्भ हो जाएगा।

SHRI A. VIJAYAKUMAR: During the peak production time, the Government of India take these vegetables from one State to another State. They are transporting like that. Will any arrangement be made in the future?

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, मैंने पहले भी एक सवाल के उत्तर में बताया था कि जब उत्पादन ज्यादा होता है तो बाज़ार में हस्तक्षेप करने की एक योजना है। इसके तहत 2015-16 में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिज़ोरम, कर्णाटक, तेलंगाना — इन राज्यों ने बाज़ार में हस्तक्षेप किया और potato, oil palm, grapes, onion और areca nut की खरीदारी की। उसके बाद 2016-17 में भी कई राज्यों, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना आदि ने इस योजना का लाभ उठाया। इस प्रकार इस तरह की योजनाओं का लाभ राज्य सरकारें उठाती हैं, लेकिन राज्य सरकारें प्रस्ताव भेजती हैं।

श्री सभापतिः उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कहा।

श्री राधा मोहन सिंहः दूसरा, राज्य सरकारें स्थान-स्थान पर ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी भी देती

हैं, जैसे पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में जब आलू का बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ तो एक तो मंडी हस्तक्षेप योजना लायी गयी और दूसरा ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दक्षिण भारत के ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी देने का काम कई राज्य सरकारें करती हैं, बंगाल ने भी किया था, उत्तर प्रदेश ने भी किया था और अधिकतर राज्य ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देते हैं।

SHRI MANISH GUPTA: Sir, I would like the hon. Minister to clarify one or two issues. The main issue is the cost of production, and this cost of production will stop the loss to farmers as we have done in West Bengal where farmers' income has been tripled. The question that I would like to ask from the Minister is this: Is there any move of the Government to reduce the cost of production of farmers by reducing GST on pesticides and fertilizers?

MR. CHAIRMAN: That is a question connected with the Finance Minister. Secondly, the Question is specific about onions, tomatoes and brinjals.

श्री राधा मोहन सिंहः किसी भी agriculture के उत्पाद पर कोई GST नहीं है, लेकिन value addition के बाद GST का प्रावधान है और जब भी मेरे पास agriculture-related किसी सैक्टर से इस प्रकार के सुझाव आते हैं, तो मैं उनको वित्त मंत्रालय को भेजता हूं।

श्री सभापतिः श्री संजय सिंह।

श्री संजय सिंहः सर, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब आपकी बाजार हस्तक्षेप नीति है, तो किसानों को अपना प्याज 50 पैसे किलो क्यों बेचना पड़ता है और उन्हें आलू सड़कों पर क्यों फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ता है? हर वर्ष जो उत्पादन होता है, क्या उसके लिए आप पहले से आकलन करके कोई नीति बनाते हैं? अगर बनाते हैं, तो हर वर्ष ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा होती है?

श्री राधा मोहन सिंहः सभापति महोदय, हमारे पास नीति है और हमारे पास technology है कि किस इलाके में, किस चीज का उत्पादन ज्यादा होता है। कहां किस चीज़ की डिमांड है, कितना उत्पादन किस एरिया में होता है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। ऐसा मोदी सरकार के आने के बाद से हुआ है और हमने एक 'चमन' योजना की शुरुआत की है। उसकी reports को हम राज्यों के साथ शेयर कर रहे हैं। यदि यह काम पहले से होता, तो आज यह सवाल खड़ा नहीं होता।

बाजार में हस्तक्षेप के संबंध में, मैं यह बताना चाहता हूं कि इसमें जो लागत मूल्य होता है, इसके हर राज्य में records भी होते हैं। यदि लागत मूल्य से दाम नीचे आता है, तो उसके अंतर का आधा हिस्सा भारत सरकार देती है। इसके संबंध में राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है। इसके बारे में मैंने बताया है और कई राज्यों का नाम भी लिया है। जब भी किसी राज्य से प्रस्ताव आता है, तो हम उसकी 24 घंटे के अंदर मंजूरी देते हैं।

MR. CHAIRMAN: Now, Q. No. 252, questioner not present. The Minister may lay the answer on the Table.